



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2015/ आषाढ़ 17, 1937

No. 240]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2015/ ASHADHA 17, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 3 जुलाई, 2015

सं. टीएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस.- पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और 'महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' के खंड 1.2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, 31 मार्च 2005 को आदेश सं. टीएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस

कोरम

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जुलाई 2015 के दूसरे वें दिन को पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निदेशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2005 को राजपत्र सं. 39 द्वारा भारत के राजपत्र में 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' अधिसूचित किए गए थे। ये दिशानिर्देश 31 मार्च 2005 से प्रभावी हुए थे जैसाकि दिशानिर्देशों के खंड 1.2 में विनिर्दिष्ट किया गया है, 5 वर्षों की अवधि अर्थात् 31 मार्च 2010 तक प्रभावी रहे हैं, जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले समीक्षा अथवा विस्तार नहीं किया जाता है।

2. पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पत्र सं. 8(1)/2004-टीएमपी दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति जारी की थी जिसे 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015' कहते हैं, और प्राधिकरण को निदेश दिया था कि तदनुसार तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाए। तदनुसार, 'महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015' नामक महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क नीति 27 जनवरी 2015 को राजपत्र सं. 30 द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण (भाग III खंड 4) में अधिसूचित की गई है। उक्त महापत्तन न्यासों हेतु प्रशुल्क नीति, 2015 दिनांक 13 जनवरी 2015 से प्रभावी हुई थी, जैसाकि एमओएस द्वारा अपने पत्र दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा निदेश दिया गया था। उक्त प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 1.1 के अनुसार, यह महापत्तन न्यासों पर लागू है। प्रशुल्क नीति के खंड 1.3 में बताया गया है कि प्रशुल्क नीति 2015 बीओटी/बीओओटी प्रचालकों अथवा निजी क्षेत्र भागीदारी हेतु किसी अन्य व्यवस्था पर लागू नहीं है।

3. एमओएस द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, यह प्राधिकरण 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता समय-समय पर विस्तारित करता रहा है। पिछली बार, उक्त दिशानिर्देशों की वैधता 1 जनवरी 2015 से 12 जनवरी 2015 तक महापत्तन न्यासों हेतु और 2005 दिशानिर्देशों के अधीन वर्तमान में शासित महापत्तनों में प्रचालन कर रहे बीओटी टर्मिनल के लिए 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की गई थी, जैसाकि एमओएस द्वारा अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी(पीटी-II) दिनांक 2 जनवरी 2015 द्वारा सलाह दी गई थी।

4. एमओएस ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी(पीटी-II) दिनांक 12 जून 2015 द्वारा 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता 31 मार्च 2016 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की है। इसके अलावा, एमओएस ने कहा है कि यह विस्तार केवल महापत्तन न्यासों में प्रचालन कर रहे बीओटी टर्मिनलों पर ही लागू है जिनके प्रशुल्क का विनियमन उक्त 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' द्वारा शासित किया जा रहा है।

5. तदनुसार, 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' की वैधता 31 मार्च 2016 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तारित की जाती है। यह विस्तार केवल महापत्तन न्यासों में प्रचालन कर रहे बीओटी टर्मिनलों पर ही लागू है जिनके प्रशुल्क का विनियमन उक्त 'महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन हेतु दिशानिर्देश, 2004' द्वारा शासित किया जा रहा है।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/2015 (126)]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2015

**No. TAMP/21/2009-WS .—** In compliance of the direction issued by the Government of India in Ministry of Shipping and in exercise of the powers conferred under clause 1.2 of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004', the Tariff Authority for Major Ports hereby further extends the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' notified vide Order No.TAMP/23/2003-WS on 31 March 2005, as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/21/2009-WS

### QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 2nd day of July, 2015)

The 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' were notified in the Gazette of India on 31 March 2005 vide Gazette No.39 by this Authority in compliance of policy directions issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts' Act, 1963. These guidelines came into effect from 31 March 2005 and as stipulated in clause 1.2 of the guidelines, remained in force for a period of 5 years, i.e. up to 31 March 2010, unless reviewed earlier or extended by this Authority.

2.The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No. 8(1)/2014-TAMP dated 13 January 2015 issued a Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, and directed the Authority to act accordingly with immediate effect. Accordingly, the Tariff Policy for Major Port Trusts called "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015" has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 27 January 2015 vide Gazette No. 30. The said Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015 came into effect from 13 January 2015, as directed by the MOS vide its letter dated 13 January 2015. As per clause 1.1. of the said Tariff Policy 2015, it is applicable to Major Port Trusts. Clause 1.3. of the *ibid* Tariff Policy states that the Tariff Policy 2015 is not applicable to BOT/BOOT operators or any other arrangement for Private Sector Participation.

3. As advised by the MOS, this Authority extended the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' from time to time. In the last time, the validity of the said guidelines was extended by the Authority for Major Port

Trusts from 1 January 2015 to 12 January 2015 and for BOT Terminal Operators operating at Major Ports presently governed under 2005 guidelines from 1 January 2015 to 31 March 2015 or until further orders, whichever is earlier, as advised by the MOS vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG(pt-II) dated 2 January 2015.

4. The MOS vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG(Pt.II) dated 12 June 2015 has extended the validity of “Guidelines for the Regulation of tariff at Major Ports, 2004” till 31 March 2016 or until further orders, whichever is earlier. Further, the MOS has stated that the extension is applicable only to the BOT terminals operating at the Major Port Trusts whose regulation of tariff is being governed by the said “Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004”.

5. Accordingly, the validity of the ‘Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004’ is extended till 31 March 2016 or until further orders whichever is earlier. This extension is applicable only to the BOT terminals operating at the Major Port Trusts whose regulation of tariff is being governed by the said “Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004”.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2015/(126)]